करेंट अफेयर्स 25 जुलाई 2022

कोड फ्लैग करें

सिलेबस: जीएस पेपर-I और II (भारतीय आधुनिक इतिहास, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)

केंद्र सरकार द्वारा **13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किए जाने के बीच,** गृह मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया **ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सके।** इससे पहले, ध्वज केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच फहराया जा सकता था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में 7 अगस्त को पारसी बागान स्क्वायर, लोअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता में फहराया गया था।** इसमें पीले, लाल और हरे रंग की तीन क्षैतिज धारियां शामिल थीं।
- इसके बाद, 1921 में, स्वतंत्रता सेनानियों **पिंगली वेंकय्या ने महात्मा गांधी को एक और राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन का प्रस्ताव दिया, जिसमें दो लाल और हरे रंग के बैंड शामिल थे।**
- आखिरकार, कई **बदलावों के बाद, 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगा झंडा अपनाया गया।** वर्तमान ध्वज 1947 में आयोजित संविधान सभा में एक बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

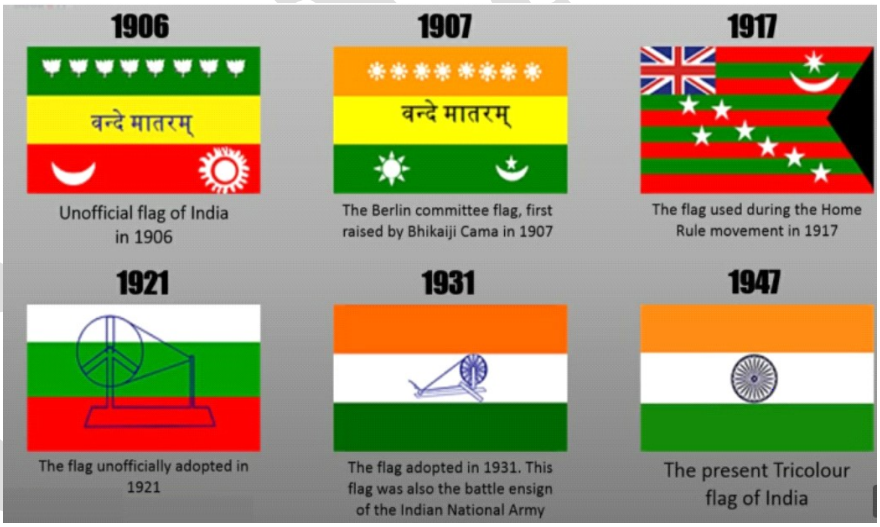

तिरंगा झंडा दिखाने के नियम

प्रतीक और नाम (रोकथाम और अनुचित उपयोग) अधिनियम, 1950

उक्त अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, राष्ट्रपति की आधिकारिक मुहर, और हथियारों के कोट को प्रतिबंधित करता है, जिसका उपयोग सरकारी विभाग करते हैं। इसी तरह, अशोक चक्र, महात्मा गांधी और प्रधान मंत्री का सचित्र प्रतिनिधित्व भी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।

• राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971

यह अधिनियम संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय मानचित्र, राष्ट्रगान और बहुत कुछ सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को अपवित्र करने पर प्रतिबंध लगाता है। जो कोई भी इन प्रतीकों का अपमान करता पाया जाता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो 3 साल तक बढ़ सकता है, जुर्माना, या दोनों।

भारतीय ध्वज कोड के बारे में

- भारतीय ध्वज का कोड **वर्ष 2002 में लागू हुआ।** कोड के अनुसार, भारत के तिरंगे झंडे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी बशर्ते कि ध्वज की गरिमा का सम्मान किया जा रहा हो।
- कोड **कानूनों, प्रथाओं और सम्मेलनों को संयोजित करने का एक प्रयास था, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा की सुरक्षा पर शासन किया था।**

• 2002 के ध्वज कोड को कई भागों में विभाजित किया गया है और नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. तिरंगे का मूल वर्णन।

2. विभिन्न निजी और सार्वजनिक निकायों और अलग-अलग शैक्षिक संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन के बारे में लागू नियम।

3. सरकार और उसके विभागों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन के बारे में लागू नियम।

ध्वज कोड की विशेषताएं:

- सरकारी निकायों, शैक्षिक संस्थानों और भारतीय ध्वज कोड पीडीएफ में सूचीबद्ध अन्य लागू संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाना। इसके अपवादों का उल्लेख प्रतीक और नाम अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में किया गया है।
- तिरंगा व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है और इसे किसी भी व्यक्ति या चीज को सलामी के रूप में नहीं डुबोया जाना चाहिए।
- सम्मान के स्थान पर कब्जा करने के लिए तिरंगे को स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।
- भारतीय ध्वज को हमेशा तेजी से फहराया जाना चाहिए, जबकि इसे औपचारिक रूप से उतारा जाना चाहिए।
- भारतीय ध्वज का उपयोग सजावट की वस्तु के रूप में किसी भी उत्सव के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- भारतीय ध्वज, यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ध्वज की गरिमा के साथ उपयुक्त तरीके से निपटाया जाना चाहिए।
- किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए, केवल उन झंडे को उपयोग में लाया जा सकता है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं और उनके विशेष निशान वाले हैं।
- एक ऐसे परिदृश्य में जहां राज्य के प्रमुख की मृत्यु होती है या राज्य के अंतिम संस्कार के दौरान, तिरंगे को आधे मस्तूल पर उड़ाया जा सकता है जब शोक की अवधि जारी रहती है। लेकिन, अगर इस तरह की घटना राष्ट्रीय महत्व के एक दिन के साथ मेल खाती है, जैसे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, तो राष्ट्रीय ध्वज को केवल उस इमारत में आधा झुकाहुआ फहराया जाना चाहिए जहां मृत व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

सिलेबस: जीएस पेपर-III (J&K अलगाववाद, मौलिक अधिकार)

विवादास्पद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत इस साल निवारक हिरासत में लिए गए कई युवाओं के परिवारों, जो बिना किसी मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, का आरोप है कि उनके रिश्तेदारों को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए "जेलों के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था और असंगत" रखा गया था।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में

जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 एक निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत **किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है ताकि उसे किसी भी तरह से कार्य करने से रोका जा सके जो "राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए प्रतिकूल है।**

- यह उल्लेखनीय रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के समान है जिसका उपयोग अन्य राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध के लिए किया जाता है।
- यह **या तो मंडलायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश द्वारा लागू किया जाता है**, न कि विशिष्ट आरोपों के आधार पर या कानूनों के विशिष्ट उल्लंघन के लिए पुलिस द्वारा हिरासत आदेश द्वारा।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम से संबंधित मुद्दे

परीक्षण के बिना निरोध:

- पीएसए एक औपचारिक आरोप के बिना और परीक्षण के बिना एक व्यक्ति की हिरासत के लिए अनुमति देता है।

- यह पहले से ही पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति पर थप्पड़ मारा जा सकता है; एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के तुरंत बाद किसी पर।
- सामान्य परिस्थितियों के विपरीत, पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

जमानत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं:

- हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष जमानत आवेदन दायर करने का अधिकार नहीं है, और वह किसी भी वकील को हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न नहीं कर सकता है।

सीमित कानूनी उपचार:

- इस प्रशासनिक निवारक निरोध आदेश को चुनौती देने का एकमात्र तरीका हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से है।
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है।
- हालांकि, यदि आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो पीएसए के तहत एक और निरोध आदेश पारित करने और व्यक्ति को फिर से हिरासत में लेने पर सरकार पर कोई रोक नहीं है।

विवेकाधीन शक्तियां:

- जिला मजिस्ट्रेट जिसने निरोध आदेश पारित किया है, को अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है, जिसमें कहा गया है कि आदेश को "सद्भावना में किया गया" माना जाता है।
- इसलिए, अधिकारियों को किसी भी अभियोजन या किसी भी कानूनी कार्यवाही से संरक्षित किया जाता है।

पीएसए की धारा 8:

- यह निरोध के लिए कई कारण प्रदान करता है, "धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी या घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को बढ़ावा देने, प्रचार करने या बनाने का प्रयास करने" से लेकर इस तरह के कृत्यों के उकसाने, उकसाने, उकसाने और वास्तविक कमीशन तक, और इसे जिला कलेक्टरों या जिला मजिस्ट्रेटों को निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है, जिसके भीतर 12 दिन की अवधि दी जाती है, जिसके भीतर, एक सलाहकार बोर्ड को निरोध को मंजूरी देनी चाहिए।

छोटे और बड़े अपराधों के बीच कोई अंतर नहीं:

- यह सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी के लिए 1 वर्ष तक और "राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल" कार्यों के लिए 2 साल तक हिरासत की अनुमति देता है।
- इन सभी कार्रवाइयों में 1919 के रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के लिए ब्रिटिश प्रतिक्रिया के लिए एक परेशान समानता है।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीएसए के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते समय, **डीएम का कानूनी दायित्व है कि वह उस व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करे**।
- यह भी माना गया है कि जब पहले से ही पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को पीएसए के साथ थप्पड़ मारा जाता है, तो डीएम को उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए **"सम्मोहक कारणों"** को रिकॉर्ड करना पड़ता है।
- जबकि डीएम पीएसए के तहत एक व्यक्ति को कई बार हिरासत में ले सकता है, उसे बाद के निरोध आदेश को पारित करते समय नए तथ्यों का उत्पादन करना होगा।

- इसके अलावा, सभी सामग्री जिसके आधार पर निरोध आदेश पारित किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने आयोजित किया है, एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रदान किया जाना चाहिए।
- निरोध के आधार को समझाया जाना चाहिए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा समझी गई भाषा में व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए।

रूस-यूक्रेन अनाज निर्यात सौदा

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ: रूस और यूक्रेन ने शुक्रवार को तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे लाखों टन सख्त जरूरत वाले यूक्रेनी अनाज के निर्यात के लिए रास्ता साफ हो गया - साथ ही रूसी अनाज और उर्वरक - एक युद्धकालीन गतिरोध को समाप्त कर दिया गया जिसने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था।

समझौते का महत्व

- रूस और यूक्रेन एक साथ दुनिया की गेहूं की आपूर्ति के एक चौथाई से अधिक के लिए खाते हैं।
- गेहूं के वैश्विक निर्यात में रूस का हिस्सा, दुनिया की सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसल, 2020 के आंकड़ों के अनुसार कुछ 20% है, जबकि यूक्रेन 8% के लिए जिम्मेदार है।

लगभग 50 देश अपने गेहूं आयात के 30% से अधिक के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर करते हैं।

- गेहूं के अलावा, यूक्रेन दुनिया का आठवां सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है
- मकई का निर्यातक, वैश्विक निर्यात का 16% के लिए लेखांकन।
- इसके अलावा, यूक्रेन, जो सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी के तेल का 46% तक उत्पादन करता है, सूरजमुखी के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।

सौदे की शर्तें

- तुर्की और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए इस समझौते का उद्देश्य युद्धकालीन गतिरोध को समाप्त करना है जिसने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था।
- सहमत समझौते **में सुरक्षित गलियारों की स्थापना का प्रावधान है जिसके साथ यूक्रेनी जहाज ओडेसा और उसके आसपास तीन नामित काले सागर बंदरगाहों में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं।**
- यह यूक्रेन को अनाज और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के अपने वैश्विक शिपमेंट को फिर से शुरू करने की सुविधा देता है।

- यह सौदा रूस को अपने अनाज और उर्वरकों का निर्यात करने की भी अनुमति देगा।

- इसके अलावा, यह सौदा **इस्तांबुल में एक नियंत्रण केंद्र की स्थापना के लिए प्रदान करता है ताकि प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाया जा सके और समन्वय** किया जा सके और संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा स्टाफ किया जाएगा।
- जहाजों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हथियार नहीं ले जा रहे हैं।

अर्थ

- इस समझौते से अकाल की कगार पर और दिवालिया होने के कगार पर खड़े विकासशील और अल्पविकासशील देशों को लाभ होने की उम्मीद है।
- यह सौदा वैश्विक खाद्य असुरक्षा और मुद्रास्फीति की चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेगा।
- यह समझौता क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए आशा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रीलिम्स तथ्य

अफ्रीकी सूअर बुखार (ASF)

- **केरल के वायनाड जिले** में दो फार्मों से एएसएफ की सूचना मिली थी।
- यह एक **अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों में रक्तस्रावी बुखार के तीव्र रूप को संक्रमित करता है और इसकी ओर जाता है।**
- रोग की अन्य अभिव्यक्तियों में उच्च बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख की कमी, त्वचा में रक्तस्राव, उल्टी और दस्त शामिल हैं।
- एएसएफ मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है क्योंकि यह केवल जानवरों से अन्य जानवरों में फैलता है।

फालबैक देयता

- वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उनके मंच पर बेची गई वस्तुओं पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।
- मसौदा ई-कॉमर्स नियमों ने "फॉल-बैक देयता" की अवधारणा पेश की, जिसमें कहा गया **है कि ई-कॉमर्स फर्मों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि उनके मंच पर एक विक्रेता लापरवाह आचरण के कारण माल या सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है, जिससे ग्राहक को नुकसान होता है।**

सरना धर्म की मांग

- झारखंड **, ओडिशा, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल** राज्यों में जनजातीय समुदाय केंद्र से मांग कर रहे हैं कि वे अपने धर्म को **'सरना'** के रूप में मान्यता दें और आगामी जनगणना में उनकी गणना सुनिश्चित करें।
- मांग **औपचारिक मान्यता के अभाव में पहचान, संस्कृति और जीवन के पारंपरिक तरीके के नुकसान** पर चिंताओं से उपजी है, जिससे अधिकांश आदिवासी रूपांतरण के प्रयासों के लिए कमजोर हो जाते हैं।
- सरना विश्वास के अनुयायी प्रकृति के लिए प्रार्थना करते हैं।
- विश्वास का पवित्र ग्रेल **"जल, जंगल, ज़मीन" है और इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों से प्रार्थना करते हैं।**